By.
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-1

Topic-Problems of Nation-Building

Class-12th

Date-17-01-2022

राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएँ :-
(Nation-Building and its Problems)

बँटवारे की त्रासदी तथा शरणार्थियों की समस्या :-

विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ देश स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान में हिन्दुओं की हत्याएँ हुईं जिससे बहुत भारी संख्या में लोगों ने भारत में शरण ली। पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिन्दुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल व असम में शरण ली। पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी व सिन्धी हिन्दुओं ने पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्रों, जैसे- पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बम्बई व दिल्ली में शरण ली। इन्हें

शरणार्थी कहा गया। अब उनके पुनर्वास की गम्भीर समस्या पैदा हुई।

शरणार्थियों के आने के साथ भारत के मुसलमानों की विशाल संख्या पलायन करके पाकिस्तान चली गई लेकिन इस घटना ने साम्प्रदायिक दंगों को भड़का दिया। भारत व पाकिस्तान के बीच 19 जुलाई, 1948 को एक समझौता हुआ। समझौते के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो लोग इस तारीख से पूर्व भारत आ गए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी अर्थात् कि वह तब से यहाँ साधारणतया वास कर रहे हों लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए, उन्हें नागरिकता नहीं जाएगी यदि उन्होंने संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर अपना पंजीकरण करा लिया

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च, 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन वह नागरिक हो सकता है यदि वह पाकिस्तान

की सरकार से स्थायी पुनर्वास का अनुमति पत्र लेकर 19 जुलाई, 1948 से पूर्व लौट आया हो और यहाँ वास कर रहा हो। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो उसने भारत में संबंधित सरकारी अधिकारी से आवेदन करके अपना पंजीकरण करा लिया हो।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अनेक काम किए गए, जैसे- बहुत सस्ती दर पर भूमि या आवासीय मकानों का आवण्टन, कार्यालयों में नौकरियाँ, कोई धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की सम्पत्ति को खाली पड़ी सम्पत्ति घोषित करके जब्त कर लिया गया। बाद में उसकी नीलामी की गई। निस्सन्देह 1947 से 1952 तक का समय इस विकट समस्या से निपटने में निकल गया। धीरे-धीरे स्थिति काबू में आई। परंतु यह समस्या अब भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। वर्तमान सरकार द्वारा एन.आर.सी व सी.ए.ए के संबंध में लिए गए निर्णय जिस तरह राजनीति का शिकार हो गया, उससे तो यही लगता है कि यह समस्या अब भी अधिक तौर पर गंभीर है।